

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर-चूरू

(पीठासीन अधिकारी -अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-4/12/2024

जीसीएमएस सं०.....

- 1 लिछमा पत्नि देदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूंकर तह. बीदासर जिला चूरू
- 2 चन्दाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूंकर तह. बीदासर जिला चूरू
- 3 गुमानाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूंकर तह. बीदासर जिला चूरू
- 4 कुम्भाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम दूंकर तह. बीदासर जिला चूरू

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1 अमराराम भामू पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम दूंकर तह. बीदासर जिला चूरू
- 2 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तह. बीदासर जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित

प्रार्थी अधि०:-श्री मोहम्मद शाहिद

अप्रार्थी अधिवक्ता- रघुवीर भामू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:निर्णय:-

दिनांक 28-3-25

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 982/973 रकबा 3.8192 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम दूंकर तहसील बीदासर में पहुँच के प्रयोजन हेतु खसरा संख्या रास्ता सड़क कटाणी मार्ग तक पहुँच हेतु खसरा नम्बर 1131/373 रकबा 0.0353 हैक्टेयर रास्ता की शकल के रूप में मौजूद है जिस पर ब्लॉक रोड़ बनी हुई है प्रार्थीगण के अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है खसरा नम्बर 1131/383 रकबा 0.0353 हैक्टेयर को रास्ता के रूप में रिकॉर्ड में अभिलिखित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 बाद असागतन-वकालतन अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 बैंक वित्तीय संस्था है जिसके अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि अन्य खसरों के साथ रहन दर्ज है।
3. प्रकरण में तहसीलदार बीदासर से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जाँच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार बीदासर द्वारा दिनांक 05.02.2025 को रिपोर्ट मय फर्द मौका जाँच रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की जो कि शामिल मिसल की गई।
4. प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना-पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर, चूरू

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है :-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या  
(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जाँच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।



सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी  
बीकानेर (दुब)

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्घरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

**68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

**69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

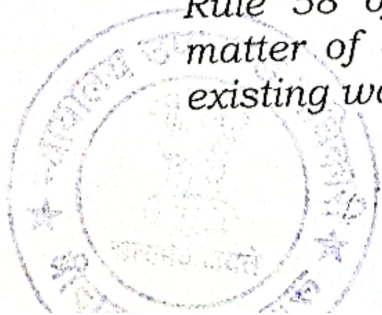
(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.


**70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

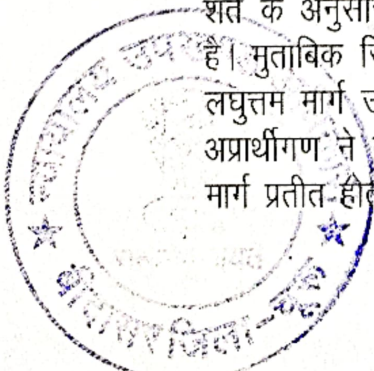



  
उपपरिवर्तन अधिकारी  
बीदासर (पूर्व)

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफ्त हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार हैं-
1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
  2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
  3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।
7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार बीदासर की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 05.02.2025 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है प्रार्थी की आराजी तक पहुँचने हेतु रिकॉर्ड में दर्ज पहुँच रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है।
8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 05.02.2025 प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर कोई लघुत्तम मार्ग उपलब्ध नहीं है। उक्त आवेदित मार्ग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत-हीला है।



  
उपलब्ध अधिकारी  
(बीदासर, राज.)

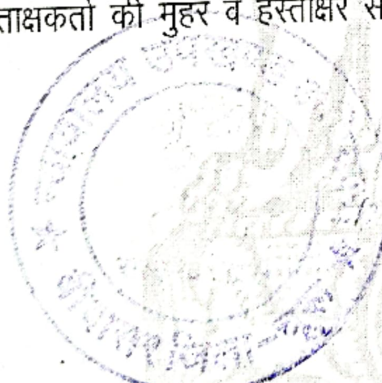
9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 05.02.2025 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से पहुँच नही होने तथा आवेदित रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251-क काबिल-ऐ स्वीकार है। अतः दिनांक 05.02.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

### आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बीदासर को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 05.02.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट में इंगित एरो → से प्रदर्शित खसरा नम्बर 1131/373 रकबा 0.0353 सम्पूर्ण खसरा को राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68-70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये अप्रार्थी स. 02 का हित अप्रार्थी स.1 के सहखातेदारी के खसरा 1133/373 पर प्रभारित करतते हुए नियमानुसार खसरें को रास्ता के रूप में खाता संख्या 01 सिवायचक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। दिनांक 05.02.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार बीदासर को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28/2/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(अमीलाल यादव आर.ए.एस.)

उपरखण्ड अधिकारी  
बीदासर - बुरु  
बीदासर (रु)

सत्यमेव जयते